INDEX

Name	Page No.
1. Haryana Civil Service Rule for Group 'B' Employees (Law Officer)	1-23
2. Haryana Civil Service Rule for Group 'B' Employees (Establishment)	24-43
3. Haryana Civil Service Rule for Group 'C' Employees (Head Quarter)	44-61
4. Haryana Civil Service Rule for Group 'C' Employees (Field)	62-79
5. Haryana Civil Service Rule for Group 'D' Employees	80-102

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 अक्तूबर, 2001

सं० सा० का० नि० 23/संवि०/अनु० 309/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अभियोजन विधिक (ग्रुप-ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

भाग-I—सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य अभियोजन विधिक (ग्रुप-ख) सेवा नियम, 2001, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, — परिभाषाएं।

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी/अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक अभियोजन, हरियाणा;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(ङ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र, (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(च) सेवा से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य अभियोजन विधिक (ग्रुप-ख) सेवा।

भाग-II—सेवा में भर्ती

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में बताए गए पद होंगे : पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो जनवरी, 1962 के प्रथम दिन से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलवी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु।

5. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा उप जिला न्यायवादी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत अन्तिम तिथि को नियत की गई सत्ताईस वर्ष से कम या चालीस वर्ष से अधिक आयु का हो।

(2) कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा सहायक जिला न्यायवादी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयोग या किसी भर्ती प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत अन्तिम तिथि को ईक्कीस* वर्ष से कम और चालीस वर्ष से अधिक की आयु का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएगी।

परन्तु अस्थाई नियुक्तियों, चार मास से अनधिक अवधि के लिए निदेशक द्वारा की जाएगी।

* अधिसूचना संख्या सा0का0नि01/संवि0/अनु0309/2004 दिनांक 2 जनवरी, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो : योग्यताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी। यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

8. कोई भी व्यक्ति— अयोग्यताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,— भर्ती का ढंग।

(क) उप जिला न्यायवादी की दशा में—

(i) 25% सीधी भर्ती द्वारा, तथा

(ii) 75% प्रतिशत सहायक जिला न्यायवादियों में से पदोन्नति द्वारा, या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) सहायक जिला न्यायवादी की दशा में सभी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

(2) पदोन्नति द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्ति, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और कोई भी व्यक्ति केवल ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के दावे का हकदार नहीं होगा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा : परिवीक्षा।

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि, की ओर गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा;

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक रहा हो तो—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो तो उसे स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है, या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्ति की गई हो

तो उसे उसके पूर्व पद पर परिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्ध तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी : ज्येष्ठता।

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नानुसार निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे;

(घ) विभिन्न संवर्गों में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता उनके वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी। अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु से बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा। सेवा करने का दायित्व।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा करने के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(i) कोई कम्पनी संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो, अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा मामले। 13. (1) वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए तत्समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों, अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को प्राईवेट प्रेक्टिस करने का अधिकार नहीं होगा।

अनुशासन, शास्ति तथा अपीलें। 14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बधित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट है।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट (घ) में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना। 15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, टीका लगवायेगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ। 16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा-स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति। 17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्ध तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

20. हरियाणा राज्य अभियोजन विधिक सेवा (ग्रुप ख) नियम 1979, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1.	उप जिला न्यायवादी	25	90	115	8000-275-10200-दक्षतारोध-275-13500 रुपए
2.	सहायक जिला न्यायवादी	129	200	329	6500-200-8500-दक्षतारोध-200-10500+200 रुपए विशेष वेतन

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।
1	2	3	4
1.	उप जिला न्यायवादी	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री; (ii) जिसने कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए बार में अधिवक्ता या अभियोजक के रूप में (प्रैक्टिस) विधि व्यवसाय किया हो; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी।	पदोन्नति द्वारा: जिसने कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए सहायक जिला न्यायवादी के रूप में कार्य किया हो; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) जिसने कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए सहायक जिला न्यायवादी के रूप में कार्य किया हो; या (ii) जिसने कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए बार में अधिवक्ता या अभियोजक के रूप में (प्रैक्टिस) विधि व्यवसाय किया हो; या (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी।
2.	सहायक जिला न्यायवादी	*(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (व्यावसायिक) की डिग्री ; (ii) बार कौंसिल में वकील के रूप में पंजीकृत होना चाहिए ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी ।	

* अधिसूचना संख्या सा०का०नि०8/संवि०/अनु0309/2004 दिनांक 13 जनवरी, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम ४ (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1. 2.	उप जिला न्यायवादी सहायक जिला न्यायवादी	सरकार	1. छोटी शास्तियां— (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघना द्वारा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय की हुई धन संबंधी हानि पूरी की या उसके भाग की वेतन से वसूली; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना;	निदेशक	सरकार
			2. बड़ी शास्तियां— (vक) संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकना; (vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसके भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;	सरकार	—

1	2	3	4	5	6
			(vii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिसे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसी जिसे ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा;	सरकार	—
			(viii) अनिवार्य सेवा निवृति;		
			(ix) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः अयोग्यता नहीं होगी;		
			(x) सेवा पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये, सामान्यतः अयोग्यता होगी।		

परिशिष्ट ब

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश पारित करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	उप जिला न्यायवादी	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उस अनुज्ञेय सामान्य अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना,	सरकार	—
2	सहायक जिला न्यायवादी	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने पर अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।		

बी० डी० ढालिया,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 10th October, 2001

No. G.S. R. 23/Const./Art. 309/2001.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment, and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Prosecution Legal (Group B) Service, namely :—

PART I -GENERAL

1. (1) These rules may be called the Haryana State Prosecution Legal (Group B) Service Rules, 2001. *Short title and commencement.*

(2) They shall come into force at once.

2. In these rules, unless the context otherwise requires, — *Definitions.*

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission ;

(b) "direct appointment" means an appointment made otherwise than by promotion or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;

(c) "Director" means the Director of Prosecution, Haryana ;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(e) "recognised University" means—

(i) any University incorporated by law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other University which is declared by the Government to be a recognised University for the purposes of these rules;

(c) "Service" means the Haryana State Prosecution Legal (Group B) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the post shown in Appendix A to these rules: *Number and Character of posts.*

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reductions in, the number of

such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia or Malawi, zaire or Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d), or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic officer of the University, college, school or institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or in Institution.

Age.

5. (1) No person shall be appointed by direct recruitment to the post of Deputy District Attorney who is less than twenty-seven years or more than forty years of age on the last date fixed for the submission of applications to the Commission or any other recruiting authority.

(2) No person shall be appointed by direct recruitment to the post of Assistant District Attorney who is less than twenty-one* years or more than forty years of age on the last date fixed for the submission of applications to the Commission or any other recruiting authority.

Appointing Authority.

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Government:

Provided that temporary appointments for a period not exceeding four months may be made by the Director.

* Substituted vide notification No. G.S.R. 14/Const./Art. 309/2004, dated 2nd January, 2004

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made, —

(a) in case of Deputy District Attorney—

(i) 25% by direct recruitment; or

(ii) 75% by promotion from amongst Assistant District Attorneys; or

(iii) by transfer or deputation of an officer already in the Service of any State Government or the Government of India;

(b) in the case of Assistant District Attorneys all the posts shall be filled in by direct recruitment.

(2) Appointment to any post in the Service by promotion shall be made on seniority-cum-merit basis and no person shall be entitled to claim promotion on the basis of seniority alone.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that—

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of appointment by transfer at the discretion of appointing authority be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may—

(a) if such person is appointed by direct recruitment dispense with his service; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment—

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory—

(i) dispense with his services if appointed by direct recruitment, or if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority of members of Service.

11. The seniority *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of their continuous service on any post in the Service :

Provided that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member a, pointed by transfer ;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same , the older member shall be senior to the younger.

Liability to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government, a Municipal Committee or a local authority within the State of Haryana ; or

(ii) the Central Government, or a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any Organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Leave, Pension and other matters.

13. (1) In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

(2) No member of the Service shall have the right or private practice.

Discipline, Penalities and Appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalities and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalities which may be imposed the authority empowered to impose such penalities and the appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these Rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of Sub-rule (1) of Rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time, shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special Provision.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes or Ex-servicemen, Physically Handicapped persons or any other class of category or persons, in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time :

Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty percent at any time.

Repeal and savings.

20. The Haryana State Prosecution Legal (Group-B) Service Rules, 1979, are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Appendix A

(See rule 3)

Serial Number	Designation of Posts	Number of Posts Permanent	Temporary	Total	Scale of Pay
1	2	3	4	5	6
1.	Deputy District Attorneys	25	90	115	Rs. 800-275-10200-EB-275-13500
2.	Assistant District Attorneys	129	200	329	Rs. 6500-200-8500-EB-200-10500+200 Special Pay

Appendix B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Deputy District Attorney	(i) Degree of Bachelor of Law from recognized University; (ii) who has practised as an advocate or a pleader at the Bar for a period of not less than five years; (iii) Hindi upto Matric standard	for promotion who has worked as Assistant District Attorney for a period of not less than five years. for transfer or deputation (i) who has worked as Assistant District Attorney for a period of not less than five years; or (ii) who has practised as an advocate or the pleader at the Bar for a period of not less than five years; or (iii) Hindi upto Matric standard.
2.	Assistant District Attorney	*(i) Degree of Bachelor of Laws(Professional) of a recognised University, (ii) Should have enrolled as an Advocate with Bar Council: (iii) Hindi upto Matric Standard.	

*Substituted vide notification No.G.S.R.2/Const./Art.309/2004, dated 13th January, 2004

Appendix C

(See rule 14(1))

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1.	Deputy District Attorney	Government	**1. Minor Penalties** (i) Warning with a copy in the personal file (character role); (ii) Censure; (iii) withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a Company and Association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and (v) withholding of increments without cumulative effect.	Director	Government
2.	Assistant District Attorney		**2. Major Penalties** (vi) withholding of increments with cumulative effect. (vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay; (vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion	Government	—

1	2	3	4	5	6
			of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service; (viii) compulsory retirement; (ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government; (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.		

Appendix D

(See rule 14(2))

Sr. No.	Designation of Posts	Nature of Order	Authority empowered to make the orders	Appellate authority
1	2	3	4	5
1.	Deputy District Attorney	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Government	—
2.	Assistant District Attorney	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		

B.D. DHALIA,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Administration of Justice Department.

37640—Prine—H.G.P., Chd.

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 नवम्बर, 1997

सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 94/संवि॰/अनु॰ 309/97.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा निदेशक, अभियोजन विभाग राजपत्रित (ग्रुप-ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग-I—सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा अभियोजन विभाग राजपत्रित (ग्रुप-ख) सेवा नियम, 1997 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी/अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक अभियोजन, हरियाणा;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई-संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि-पत्र, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय; या

(iii) कोई भी अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(ठ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा अभियोजन विभाग शासकीय (ग्रुप-क) सेवा।

भाग-II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताए गए पद होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

4. सेवा में पदों पर नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी।

अर्हताएं।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना-3 में तथा पदोन्नति की दशा में उपर्युक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो।

निरर्हताएं।

6. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

7. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी:—

(क) प्रशासनिक अधिकारी की दशा में,—

(i) अधीक्षकों/उप अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) अधीक्षक की दशा में,—

(i) उप अधीक्षक/निजी सहायक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा,

(2) स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जायेगी, जबकि पदोन्नति के लिये कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होगा ।

(3) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हो ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ही अपने-अपने संवर्गों में ऐसी पदोन्नतियों का अधिकार ज्येष्ठता प्रदान नहीं करेगी ।

8. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा ।
परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया हो परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, जब तक वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्टि किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—

(क) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ख) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्त प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति या नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ;

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसे संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति से कार्यवाही कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसको परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता। 9. (1) सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी,—

(क) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिससे वे पदोन्नति या स्थानान्तरित किये गए थे।

(ग) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व।

10. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, सेवा करने के लिये दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण के पास है ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

11. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए गए या बनाए गए हों, अथवा उसके बाद अपनाए या बनाए जायें ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

12. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट-"ग" में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) पंजाब सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट (घ) में बताया गया है ।

टीका लगाना।

13. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, टीका लगवायेगा या पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

14. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति।

15. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

16. इन नियमों में किसी बात के होते भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

17. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

निरसन तथा व्यावृत्ति।

18. सेवा में लागू इन नियमों के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के प्रारम्भ होने से तुरन्त पूर्व लागू थे, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश अथवा की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट "क"

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	प्रशासकीय अधिकारी	—	1	1	2200—75—2800—द.रो.—100—4000 रुपए
2	अधीक्षक	—	1	1	2000—60—2300—75—2900—द.रो.—100—3500 रुपए

परिशिष्ट "ख"

(देखिए नियम 5)

क्रम संख्या	पदनाम	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव
1	2	3	4
1	प्रशासकीय अधिकारी	हरियाणा सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग में अधीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	अधीक्षक के रूप में दो वर्ष या उप-अधीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।
2	अधीक्षक	हरियाणा सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में उप-अधीक्षक या निजी सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।	उप-अधीक्षक/निजी सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव और निजी सहायक को सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव या सहायक के कार्य का हिस्सा संभाला होना चाहिए।

परिशिष्ट "ग"

[देखिए नियम 12(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति अधिरोपित करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	प्रशासकीय	सरकार	1. छोटी शास्तियां— (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संस्था तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी पूरी हानि को या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ; 2. बड़ी शास्तियां— (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी	निदेशक	सरकार
2	अधीक्षक				

1	2	3	4	5	6
			अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं, और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान ग्रेड पद या सेवा पर जिसमें वह अवनत किया गया था पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ; (ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ; (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निर्योग्यता नहीं होगी ; (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतया निर्योग्यता होगी।	सरकार	—

1	2	3	4	5	6
			अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं, और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान ग्रेड पद या सेवा पर जिसमें वह अवनत किया गया था पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ; (ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ; (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी ; (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतया निरर्हता होगी।	सरकार	—

परिशिष्ट "घ"

[देखिए नियम 12(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश पारित करने के लिये प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1 2	प्रशासकीय अधिकारी अधीक्षक	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उस अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना।	सरकार	—
		(ii) सेवा के किसी सदस्य की, उसे वार्धिक्य के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति		

के० जी० वर्मा,

सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 21st November, 1997

No. G. S. R. 94/Const/Art.309/97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of Service of persons appointed, to the Haryana Prosecution Department Ministerial (Group-B) Service, namely :—

PART-I GENERAL

Short title and commencement.

1. (*1*) These rules may be called the Haryana Prosecution Department, Ministerial (Group-B) Service Rules, 1997.

(*2*) They shall come into force at once.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) 'Commission' means the Haryana Public Service Commission;

(*b*) 'direct Recruitment' means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;

(*c*) 'Director' means the Director of Prosecution, Haryana.

(*d*) 'Government' means the Haryana Government in the Administrative Department;

(*e*) 'Institution' means,—

(*i*) Any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(*ii*) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(*f*) 'Recognised University' means,—

(*i*) any university incorporated by law in India; or

(*ii*) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1997, by the Punjab, Sind or Dacca University; or

(*iii*) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules;

(g) 'Service' means Haryana Prosecution Department Ministerial (Group-B) Serivce.

PART-II RECRUITMENT OF SERVICE

Number and Character of posts.

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Appointing authority.

4. Appointments to the post in the service shall be made by the Government:

Qualifications.

5. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in columns 3 of Appendix B to these rules in case of tansfer on deputation and these specified in column 4 of the aforesaid Appendix in case of promotion.

Dis-qualifications.

6. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spous living ; or

(b) who having a spous living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable tosuch person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

7. (1) Recruitment to the Service shall be made,—

(a) in the case of Administrative officer,—

(i) by promotion from amongst the Superintendents/ Deputy Superintendent; or

(ii) by transfer or on deputation of an officer/official already in service of any State Government or Government of India;

(b) In the case of Superintendent,—

(i) by promotion from amongst Deputy Superintendent/ Personal Assistant; or

(ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) The appointment by transfer or deputation shall be made only in exceptional circumstances when a suitable person is not available for promotion.

(3) All promotions, unless otherwise provided shall be made on the seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions, in respective cadre.

8. (*1*) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of one year: Probation.

Provided that:—

(*a*) any period, after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(*2*) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory it may,—

(*a*) revert him to his former post; or

(*b*) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(*3*) On the completion of the period of probation of a person the appointing authority may,—

(*a*) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(*i*) confirm such person from the date of his appointment if appointed against a permanent vacancy; or

(*ii*) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(*iii*) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(*b*) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—

(*i*) revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(*ii*) extend his period of probation and thereafter pass such orders, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided, that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

9. Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the service the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:—

(a) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(b) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such member in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(c) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in this previous appointment and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

10. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company, an assoication or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled, by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

11. In respect of pay, leave pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India, or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

12. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time; — **Discipline, penalties and Appeals.**

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix 'C' to these rules ;

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the Appellate Authority shall also be as specified in Appendix D to these rules ;

13. Every member of the Service shall get himself vaccinated or revaccinated if and when the Government so directs by special or general order. — **Vaccination.**

14. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established. — **Oath of alligiance**

15. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with any respect to any class or category of persons. — **Power of relaxation.**

16. Nothwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so. — **Special provisions.**

17. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the order issued by the State Government in this regard, from time to time. — **Reservation.**

18. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed : — **Repeal and savings.**

Provided that any order made or action taken under the rules so repealded shall be deemed to have been made or taken the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(*See* Rule 3)

Sr. No.	Designation of post	Number of post Permanent	Number of post Temporary	Total	Scale of Pay
1	2	3	4	5	6
1	Administrative Officer	—	1	1	Rs. 2200—75—2800—EB—100—4000
2	Superintendent	—	1	1	Rs. 2000—60—2300—75—2900—EB—100—3500

APPENDIX B

(*See* Rule 5)

Sr. No.	Designation of the post	Academic qualifications and experience, if any, for appointment by transfer/deputation	Academic qualifications and experience, if any, for appintment by pomotion
1	2	3	4
1	Administrative Officer	Five years experience as Superintendent in a Department of Haryana Government or Central Government	Two years experience of the post of Superintendent or 5 years experience as Deputy Superintendent
2	Superintendent	Three years experience as Deputy Superintendent or Personal Assistant in a Department of Haryana Government or Central Government	Two years experience as Deputy Superintendent or Personal Assistant and Personal Assistant should have experience of two years as Assistant or by sharing the work of an Assistant.

APPENDIX C

[*See* Rule 12(1)]

Sr. No.	Designation of officer	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
			Minor Penalties		
1	Administrative Officer	Government	(i) warning with a copy on the personal file (Character roll)	Director	Government
			(ii) censure;		
2	Superintendent		(iii) withholding of promotion		
			(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Govt. or a State Government or to a Company and Association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Govt. or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and		
			(v) withholding of increments of pay without cummulative effect;		
			Major Penalties		
			(vi) withholding of increments with cummulative effect;		
			(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified	Government	—

1	2	3	4	5
			period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;	
			(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee in the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;	
			(ix) compulsory retirement ;	
			(x) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;	
			(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.	

APPENDIX D

[*See* Rule 12(2)]

Sr. No.	Designation of Officer	Nature of order	Authority competent to make order	Appellate Authority
1	2	3	4	5
1 2	Administrative Officer Superintendent	(a) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; and (b) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Government	

K. G. VARMA,

Secretary to Government, Haryana,
Administraton of Justice Department.

THE HARYANA STATE PROSECUTION GROUP 'C'

(CLERICAL HEADQUARTERS) SERVICES RULES, 1980

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT.—(i) These rules may be called the Haryana State Prosecution Group 'C' (Clerical Headquarters) Services Rules, 1980.

(ii) They shall come into force at once.

Note.—Published vide No G.S.R. 106/Const./Art/309/80, dated 10-10-1980

2. DEFINITIONS.— In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Board" means the Subordinate Services Selection Board, Haryana;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;

(c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department.

(d) "Director" means the Director of Prosecution, Haryana;

(e) "recognised university" means :-

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result on an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University, or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purposes of these rules;

(f) "Service" means Haryana State Prosecution Group 'C' (Clerical Headquarters) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

3. NUMBER AND CHARACTER OF POSTS.— The service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to; or reduction, in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. NATIONALITY, DOMICILE AND CHARACTER OF CANDIDATES RECRUITED TO THE SERVICE.— No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is :—

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania (formerely Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawai, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging any of the to categories (b),(c),(d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate or eligibility is neccessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruting authority, but the offer of appointment may be given only after the neccessary eligibility certificate has been issued to him by the Government. (3) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal/academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. **AGE.**— No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years and more than thirty years of age on the last date of submission of application to the Board or any other recruiting authority.

6. **APPOINTING AUTHORITY.**— Appointments to the posts in the service shall be made by the Director.

7. **QUALIFICATIONS.**—No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in Appendix B to these rules.

8. **DISQUALIFICATIONS.**—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered in to or contrarted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. **METHODS OF RECRUITMENT.**—(1) Recruitment to the Service shall be made :—

(i) by promotion; or

(ii) by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

Provided further that the percentage of posts of Assistants to be filled by direct recruitment or by transfer shall not exceed twenty-five per cent :

Provided further that the percentage of posts of clerks to be filled by way of promotion from amongst restorers Group 'D' employees, shall not exceed twenty percent.

10. PROBATION.—(1) Person appointed to any post in the Service, shall remain on probation for a period of two years, if appointed by the direct recruitment and one year, if appointed otherwise ;

Provided that :—

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work is equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with this sevices ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment :—

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may :—

(a) if his work or conduct has, in its opinion; been satisfactory :—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed is against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory :—

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, or revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appionment permit if appointed otherwise ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

11. SENIORITY OF MEMBERS OF THE SERVICE.— The seniority *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that in the case of different cadres in the service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointment from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres their seniority shall be determined according to pay, preference being given to member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, than by the length of service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12. LIABILITY TO SERVE. — (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana on being ordered so to do by the appointing authority ;

(2) A member of the Service may also be deputed to service as under :—

(i) a company, association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority, within the State of Haryana ; or

(ii) the Central Government or company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body :

Provided that no member of the service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) and clause (iii) except with his consent.

13. PAY, LEAVE, PENSION OR OTHER MATTERS. — In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State legislature.

14. DISCIPLINE, PENALTIES AND APPEALS.— (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1952, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) and clause (d) of sub rule (1) of rule 10 of the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1952, and the appellate authority shall be as specified in Appendix 'D' to these rules.

15. VACCINATION.— Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated if and when the Government so direct by a special or general order.

16. OATH OF ALLEGIANCE.— Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

17. POWER OF RELAXATION .— Where the Government is of the opinion that it is necessary of expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

18. SPECIAL PROVISIONS.— Notwithstanding anything contained in these rules appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

19. RESERVATIONS.— Nothing contained in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time, under caluse (4) of article 16 of the Constitution of India.

20. REPEAL AND SAVINGS.— Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is herby repealed: Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

APPENDIX A

(See rule-5)

Serial No.	Designation of Post	Number of Posts Permanent	Temporary	Total	Scale of Pay
1	2	3	4	5	
					Rs.
1.	Deputy Superintendent	—	1	1	700-30-830/900-40-1,100-EB-50-1,250
2.	Assistant	—	4	4	525-15-600-20-660/700-30-850-EB-890-40-1,050 (with initial start of Rs. 585 per mensem)
3.	Senior Scale Stenographer	—	1	1	525-15-600-20-660-700-30-850-EB-890-40-1,050 (with initial start of Rs. 585)
4.	Steno-typist	—	1	1	400-10-490/540-15-600-EB-20-660 plus Rs. 25 special pay
5.	Clerk	—	5	5	(i) 400-10-490/540-15-600-EB-20-660 (TS)
					(ii) 480-15-600-EB-20-700-30-760 (S.G. for 20% posts)
6.	Restorer	—	1	1	400-10-490/540-15-600-EB-20-600
7.	Driver	—	1	1	420-10-490/540-15-600-EB-20-700

APPENDIX B

(See rule-7)

Serial No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Deputy Superintendent	(i) Matric (1st Division)/Higher Secondary/Intermediate 2nd Division/Graduate or equivalent (Matric for Ex-servicemen only) (ii) Eight years experience as Assistant	(i) Matric/Higher Secondary/Intermediate Graduate or equivalent (Matric for Ex-servicemen only). (ii) Eight years experience as Assistant. 1(i) Five years experience as Clerk.
2.	Assistant	(i) Matric (1st Division)/Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd Division/Graduate or equivalent (For Ex-servicemen Matric only) (ii) Knowledge of Hindi up to Matric standard (iii) 3 years experience on any post involving noting Land drafting	
3.	Senior Scale Stenographer	(i) Matric (1st Division)/Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd Division/Graduate or equivalent (For Ex-servicemen Matric only) (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard (iii) English shorthand 1[80 words] p.m. and transcription thereof at 1[25 words] p.m. (iv) Hindi shorthand at 1[64 words] p.m. and transcription thereof at 1[15 words] p.m.	(i) Matric (1st Division), Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd Division, Graduate or equivalent (For ex-servicemen Matric only). (ii) English shorthand 1[100 words] p.m. and transcription thereof at 1[25 words] p.m. (iv) Two years experiance as Juinior Scale Stenographer or four years experience as Steno-typist
4.	Steno-typist	(i) Matric 1st Division, Higher Secondary 2nd Division, Intermediate 2nd Division, Graduate or equivalent (For Ex-servicemen Matric only)	(i) Matric 1st Division/Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd Division/ Graduate or equivalent (For ex-servicemen Matric only).

1	2	3	4
		(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard	(ii) English Shorthand at [5][80 words] p.m. and transcription thereof at [1][20 words] p.m.
		(iii) English Shorthand at [5][80 words] p.m. and transcription thereof at [5][25 words] p.m.	(iii) Hindi Shorthand at [5][64 words] p.m. and transcription thereof at [5][15 words] p.m.
5.	Clerk	(i) Matric 1st Division, Higher Secondary 2nd Division, Intermediate 2nd Division, Graduate or equivalent (For Ex-servicemen Matric only)	[3](i) Matric or its equivalent
		(ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard	(ii) 5 years experience as Restorer or Group 'D' employees, and
		(iii) He/She will be required to qualify the English/ Hindi Type test at the speed of [5][20/25 words]	(iii) Knowledge of Hindi upto Matric
6.	Restorer	(i) Matric or above	(i) Matric or above
		(ii) Hindi upto Matric Standard	(ii) Three years experience as peon
*7.	Driver	(i) Primary or above	(i) Primary or above
		(ii) Working knowledge of Hindi	(ii) Working knowledge of Hindi
		(iii) Driving licence of light motor vehicle	(iii) Driving licence of light motor vehicle
		(iv) Three years practical experience of driving	(iv) Three years practical experience of driving.
		—	(v) Already in the service of the State Government.

1. Sub. by GSR. 56, dated 5-8-83.
2. Sub. by *ibid.*
3. Omitted by *ibid.*
4. Ins. by *ibid.*
5. Sub. by GSR. 84, dated 11-11-85 w.e.f. 01-01-80.

[redacted]

APPENDIX C

(See rule 14(1))

Serial No.	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1		2	3	4	5
1.	Deputy Superintendent	Director	(a) Warning with a copy on personal file		
			(b) Censure		
2.	Assistant		(c) Withholding of increments or promotion including stoppage at an efficiency bar ;	Director	Government
3.	Senior Scale Stenographer				
4.	Steno-typist		(d) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of orders ;		
5.	Clerk				
6.	Restorer		(e) Reduction to a lower post or time scale or to a lower stage in a time scale		
[1]7.	Driver		(f) Removal from the service which does not disqualify from future employment ;		
			(g) Dismissal from the service which does not ordinarily disqualify from future employment ;		

1. Ins. by GSR. 56, dated 5-8-1983.

APPENDIX D

(See rule 14(2))

Serial No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make order	Appellate Athority
1	2	3	3	4
1.	Deputy Superintendent	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary additional pension admissible under the rules governing pension	—	—
2.	Assistant			
3.	Senior Scale Stenographer	(ii) Terminating the appointment of a member of the Service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation	Director	Government
4.	Steno-typist			
5.	Clerk			
6.	Restorer			
[1]7.	Driver			

1. Ins. by GSR. 56, dated 5-8-83.

36074—Prosecution—H.G.P., Chd.

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 24th May, 1996

No. G.S.R. 39 /Const./Art. 309/96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Prosecution Group 'C' (Clerical Headquarters) Service Rules, 1980, namely :—

1. These rules may be called the Haryana State Prosecution Group 'C' (Clerical Headquarters) Service (Amendment) Rules, 1996.

2. In the Haryana State Prosecution Group 'C' (Clerical Headquarters) Service Rules, 1980, in Appendix B.—

(a) against serial No. 1,—

(i) under column 2, after the words and figures "Intermediate 2nd Division", the sign, figures brackets and words "/10+2 (vocational) 2nd Division" shall be inserted ;

(ii) under column 3, after the word "Intermediate", the sign, figures, brackets and words "/10+2 (vocational) 2nd Division" shall be inserted ;

(b) against serial number 2,—

(i) under column 2, after the words and figure "Intermediate 2nd Division", the sign, figures, brackets and words "/10+2 (vocational) 2nd Division" shall be inserted ;

(ii) under column 3, after the words and figures "Intermediate 2nd Division", the sign, figures, brackets and words "/10+2 (vocational) 2nd Division" shall be inserted ;

(c) against serial number 3,—

(i) under column 2, after the words and figure "Intermediate 2nd Division", the sign, figures, brackets and words "/10+2 (vocational) 2nd Division" shall be inserted;

(ii) under column 3, after the words and figures "Intermediate 2nd Division", the sign, figures, brackets and words "/10+2 (vocational) 2nd Division" shall be inserted;

127

(d) against serial number 4,—

A. under column 2,—

(i) against item (i) after the words and figure "Intermediate 2nd Division", the sign, figures, brackets and words "/10+2 (vocational) 2nd Division" shall be inserted;

(ii) against item (iii), for the figures "100" and "20" the figures "80" and "15" shall respectively be substituted ;

(iii) against item (iv), for the figure "80" and "15", the figures "64" and "11" shall respectively be substi tutted ;

B. Under column 3—

(i) in item (i), after the words and figures "Intermediate 2nd Division", the sign, figures, brackets and words "/10+2 (vocational) 2nd Division" shall be inserted ;

(ii) in item (ii), for the figures "100" and "20" the figures "80" and "15" shall respectively be substituted

(iii) in item (iii), for the figures "80" and "15", the figures "64" and "11" shall respectively be substituted ;

(e) against serial number 5,—

A. under column 2—

(i) in item (i), after the words and figure "Intermediate 2nd Division" the sign, figures, brackets and words "/10+2 (vocational) 2nd Division" shall be inserted ;

(ii) for item (iii), the following item shall be substituted, namely :—

"(iii) Hindi/English typing at a speed of 25/30 words per minute respectively" ;

B. under column 3—

(i) in item (i), after the words and figures "Intermediate 2nd Division" the sign, figures, brackets and words "/10+2 (vocational) 2nd Division", shall be inserted ;

(ii) for item (iv), the following item shall be substituted, namely :—

"(iv) Hindi/English typing at speed of 25/30 words per minute.".

A. N. MATHUR,

Financial Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 नवम्बर, 2013

संख्या सा०का०नि० 30/संवि०/अनु० 309/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अभियोजन ग्रुप 'ग' (लिपिकीय मुख्यालय) सेवा नियम, 1980, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा राज्य अभियोजन ग्रुप 'ग' (लिपिकीय मुख्यालय) सेवा संशोधन नियम 2013, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य अभियोजन ग्रुप 'ग' (लिपिकीय मुख्यालय) सेवा नियम, 1980 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9क.—(1) टंकण परीक्षा लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिये सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई. टी.सी.) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तारयोग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदों के पूर्वोक्त प्रवर्गों के विरूद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्नत किए गये हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तार योग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस

नियम के उप नियम (4) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय–समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार टाइपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किया गया 'पास' प्रमाण–पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

(4) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्डप्रोसैसिंग, इन्टरनैट बराउज़िंग तथा ई–मेल मैनेजमैन्ट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाईपिंग स्पीड, चूंकि टाइपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जायेगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) देने से छूट दी जाती है :–

(i) एम.टैक./बी.टैक. (कम्प्यूटर), एम.सी.ए., बी.सी.ए. या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पॉलिटैक्निक्स से कम्प्यूटर में डिप्लोमा ;

(ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल.आई.टी.)(पूर्व डीओईएसीसी सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण–पत्र ;

(iii) एच.के.सी.एल. के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए.एल.सीज) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण–पत्र (एचएससीआईटी) ;

(iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एसईटीसी पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवा ग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) को हारट्रोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जायेगा; तथा

(v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन, ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, पैरेलइसिस ऑफ रेडयल (रेडयल नैव पॉल्ज़ि) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नैवस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेमिलनेशैन डिजेनेरेटिव डिसआर्डर्ज जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप–पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,–

I. क्रम संख्या 3 के सामने, खाना 3 के नीचे, मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(i) 10+2/स्नातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 10+2);";

II. खाना 4 के नीचे, मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(i) 10+2/स्नातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 10+2);";

III. क्रम संख्या 5 के सामने,

(क) खाना 3 के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"(i) 10+2/स्नातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 10+2);";

"(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;

"(iii) नियम 9 क के दृष्टिगत लोप कर दिया गया;";

(ख) खाना 4 के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"(i) 10+2/स्नातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 10+2);

"(ii) रेस्टोरर या ग्रुप 'घ' कर्मचारियों के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव;

"(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।"।

एस० सी० चौधरी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 8th November, 2013

No. G.S.R. 30/Const/Art.309/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Prosecution Group 'C' (Clerical Headquaraters) Service Rules, 1980, namely :—

1. These rules may be called the Haryana State Prosecution Group 'C' (Clerical Headquaraters) Service (Amendment) Rules, 2013.

2. In the Haryana State Prosecution Group 'C' (Clerical Headquaraters) Service Rules, 1980 (hereinafter called the said rules), after rule 9, the following rule shall be inserted, namely :—

"9A (1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers in the Government Departments/Organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. who have not passed the typing test till date as required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC). The Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers shall also have to qualify Stenography test as prescribed in the Service Rules.

(2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruit. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk and Steno-typists shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year, failing which he/she will be reverted back.

(3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTON) or any other agency as prescribed by the Government, as the authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as the State Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The 'pass' certificate

issued by HARTON or any other agency, as approved by the Government, would be accepted as an evidence of the fulfilment of the prescribed condition in the Service Rules.

(4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.

(5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.

(6) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) :—

(i) M.Tech./B.Tech. (Computers), MCA, BCA or Diploma in Computers from the recognized institutions *e.g.* Polytechnics;

(ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];

(iii) Haryana State – Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorized Learning Centres (ALCs) of the HKCL;

(iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of 5 years from the date of issue of such certificate by HARTON or any other agency authorized by the Government; and

(v) Physically disabled candidates *i.e.* amputation of hand (left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial Nerve (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC).".

3. In the said rules, in Appendix B :—

I. against serial number 3, under column 3, for existing item (i), the following item shall be substituted, namely :—

"(i) 10+2/Graduate or its equivalent

(for ex-servicemen 10+2 only);";

II. against serial number 4, under column 3, for item (i), the following item shall be substituted, namely :—

"(i) 10+2/Graduate or its equivalent

(for ex-servicemen 10+2 only);";

III. against serial number 5,—

(a) under column 3, for the existing items, the following items shall be substituted, namely :-

"(i) 10+2/Graduate or its equivalent

(for ex-servicemen 10+2 only);";

(ii) Knowledge of Hindi upto Metric standard;";

(iii) Omitted in view of rule 9A;";

(b) under column 4, for the existing items, the following items shall be substituted, namely :-

"(i) 10+2;

(ii) Five years experience as Restorer or Group 'D' employees;

(iii) Knowledge of Hindi upto Metric standard.".

S. C. CHOUDHARY,
Additional Chief Secretary to Government,
Haryana, Administration of Justice Department.

[Published in the Haryana Government Gazette, Legislative Supplement, dated the 14th August, 1979]

PART III

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 10th August, 1979

No. G.S.R. 81/Const./Art. 309/79.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, regulating recruitment and conditions of Service of persons appointed, to the Haryana State Prosecution Group C (Clerical Field) Service, namely :—

PART I—GENERAL

Short title, commencement and application.

1. (1) These rules may be called the Haryana State Prosecution Group C (Clerical Field) Service Rules, 1979.

(2) They shall come into force at once.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board" means the Subordinate Services Selection Board, Haryana;

(b) "Direct recruitment" means any appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service, of the Government of India or any State Government ;

(c) "Director" means the Director of Prosecution, Haryana;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(e) "Service" means the Haryana State Prosecution, Group C (Clerical Field) Service ;

(f) "recognised university" means,—

(i) any university incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of a degree, diploma certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ;

(iii) any other University which is decided by Government to be a recognised University for the purpose of these rules.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reduction in the number of such

posts or to create new posts with different designation and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the service.

4. (1) No person shall be appointed to the Service, unless he is,—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to category (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to the Service by direct recruitment unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are un-connected with his university, college, school or institution.

Age

5. No person shall be appointed to the Service by direct recruitment who is less than 17 years or more than 27 years of age on the last date fixed for submission of application to the Board or any other recruiting authority.

Appointing Authority.

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Director.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in Appendix B to these rules.

Disqualification.

8. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

217

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made— Method of recruitment.

(i) by promotion ; or

(ii) by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the Service of any State Government or the Government of India.

(2) When any vacancy occurs or is about to occur in the Service, the appointing authority shall determine the manner in which such vacancy shall be filled.

(3) Appointments by promotion shall be made on the basis of seniority and fitness to the post, and no person shall be entitled to claim promotion as a matter of right and on the basis of seniority alone.

(4) The percentage of appointment to the various posts in the Service shall be made as under :—

(a) In the case of clerks—

(i) 20% by promotion from class IV employees who are matriculates or posses equivalent qualifications and have worked as such for not less than a period of five years ;

(ii) 80% by direct recruitment or by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(b) In the case of other posts—

(i) 75% by promotion from clerks ; provided they fulfil the qualifications 'as prescribed in Appendix B' ;

(ii) 25% by direct recruitment or transfer.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise : Probation.

Provided that—

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as a period spent on probation but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services, and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

3. On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ;

or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory—

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit ; or

(iii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension, if any shall not exceed three years.

Seniority of the members of Service

11. The seniority *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board, shall not be disturbed in fixing the seniority ;

2M

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointment from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana. Liability to serve.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority within the State of Haryana ; or

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) and (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature. Leave, Pension or other matters.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1952, as amended from time to time : Discipline, penalties and appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall,

9

subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix 'C' to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clauses (c) and (d) of sub-rule (1) of rule 10 of the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1952 and the appellate authority shall be as specified in Appendix 'D' to these rules.

Vaccination. 15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated if and when the Government so direct by a special or general order.

Oath of allegiance. 16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation. 17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions. 18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations. 19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time, under clause (4) of article 16 of the Constitution.

926

APPENDIX A

(*See rule 3*)

Designation of posts	Number of posts: Permanent	Temporary	Total	Scale of pay
1	2	3	4	5
1. Head Clerk-cum-Accountant	...	11	11	Rs. 160—10—280/15—400
2. Stenographer-cum-Librarian	...	11	11	Rs. 160—10—280/15—400
3. Clerks	13	16	29	Rs. 110—4—130/5—160/5 — 225 (with two advance increments to graduates)

APPENDIX B

(See Rule 7)

Designation of posts	Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	2
1. Head Clerk-cum-Accountant	—	1. Matric *or Higher Secondary or equivalent/10+2 (Vocational). 2. 5 years experience as Clerk. 3. Knowledge of Hindi upto Matric Standard.
2. Stenographer-cum-Librarian	1. Matric/Higher Secondary or equivalent* or 10+2 (Vocational). 2. Knowledge of Hindi upto Matric 3. Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute. OR English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute.	1. Matric/Higher Secondary or equivalent* or 10+2 (Vocational). 2. Knowledge of Hindi upto Matric standard. 3. Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute. OR English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute.
3. Clerks	1. Matric/Higher Secondary or equivalent* or 10+2 (Vocational) 2. Knowledge of Hindi upto Matric Standard. 3. *Hindi/English typing at a speed of 25/30 words per minute respectively.	1. Matric/Higher Secondary or equivalent* or 10+2 (Vocational) 2. Five years experience on Class IV post. 3. Knowledge of Hindi upto Matric Standard.

*Amended vide Haryana Government Notification No. GSR 40/Const./Art. 309/96, dated 24-5-1996

APPENDIX C

(*See* rule 14)

Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5
1. **Head Clerk-cum-Accountant** 2. **Stenographer-cum-Librarian** 3. **Clerks**	Director	(a) Warning with a copy in personal file ; (b) Censure ; (c) Withholding of increments or promotion including stoppage at an efficiency bar ; (d) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of orders ; (e) reduction to a lower post or time scale or to a lower stage in a time scale ; (f) removal from the service which does not disqualify from future employment ; (g) dismissal from the service which does ordinarily disqualify from future employment.	Director	Government

939

APPENDIX D

[*See* rule 14(2)]

Designation of post	Nature of order	Authority empowered to make order	Appellate authority
1	2	3	4
1. Head Clerk-cum-Accountant 2. Stenographer-cum-Librarian 3. Clerks	(1) Reducing or withholding the amount of ordinary/additional pension admissible under the rules governing pension. (2) Terminating the appointment of a member of the Service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Director	Government

L. D. KATARIA,
Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

34025—Prose—H.G.P., Chd.

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 13th January, 1982

No. G.S.R. 13/Const./Art. 309/Amd.(1)/82.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Prosecution Group C (Clerical Field) Service Rules, 1979, namely :—

1. These rules may be called the Haryana State Prosecution Group C (Clerical Field) Service First Amendment Rules, 1982.

2. In the Haryana State Prosecution Group C (Clerical Field) Service Rules, 1979, in Appendix B, under column 2, against the post of "Head Clerk-cum-Accountant", the following entries shall be inserted, namely :—

"(1) Matric or above.

(2) Five years experience of clerical work.

(3) Knowledge of Hindi up to Matric standard.".

L. C. GUPTA,

Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

3052CS(H)—Govt. Press, Chd.

[Published in the Haryana Government Gazette, (Legislative Supplement, dated the 11th January, 1983]

PART III

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 6th January, 1983

No. G.S.R. 11/Const./Art.309/2nd Amd./83.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Prosecution Group C (Clerical Field) Service Rules, 1979, namely:—

1. These rules may be called the Haryana State Prosecution Group C (Clerical Field) Service Second Amendment Rules, 1983.

2. In the Haryana State Prosecution Group C (Clerical Field) Service Rules, 1979 (hereinafter called the said rules), in rule 5, for the figure "27", the figure "31" shall be substituted.

3. In the said rules, in Appendix B, under Column 2 for the figures "25/30", the figures "20/25" shall be substituted.

L. C. GUPTA,

Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

7369CS (H)—Govt. Press, U.T., Chd.

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 नवम्बर, 2013

संख्या सा०का०नि० 29/सवि०/अनु० 309/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अभियोजन ग्रुप ग (लिपिकीय क्षेत्रीय) सेवा नियम, 1979, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. ये नियम हरियाणा राज्य अभियोजन ग्रुप ग (लिपिकीय क्षेत्रीय) सेवा संशोधन नियम 2013, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य अभियोजन ग्रुप ग (लिपिकीय क्षेत्रीय) सेवा नियम, 1979 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"9क.– (1) टंकण परीक्षा लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिये सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तार योग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदों के पूर्वोक्त प्रवर्गों के विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्नत किए गये हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तार योग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस

नियम के उप नियम (4) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार टाईपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किया गया 'पास' प्रमाण-पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

(4) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्डप्रोसैसिंग, इन्टरनैट ब्राउजिंग तथा ई-मेल मैनेजमैन्ट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाईपिंग स्पीड, चूंकि टाईपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जायेगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) देने से छूट दी जाती है :-

(vi) एम.टैक./बी.टैक. (कम्प्यूटर), एम.सी.ए., बी.सी.ए. या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पालिटैक्निक्स से कम्प्यूटर में डिप्लोमा;

(vii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल. आई.टी.)(पूर्व डीओईएसीसी सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण-पत्र;

(viii) एच.के.सी.एल. के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए.एल.सीज) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण-पत्र (एचएससीआईटी);

(ix) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एसईटीसी पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवाग्रहण करते समय वैद्य है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) को हारट्रोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैद्य माना जायेगा; तथा

(x) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, पैरेलइसिस ऑफ रेडियल (रेडियल नैव पॉलिज) दोनों में से कोई ऊपरी अंग। नेंवस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेविलनेशन डिजेनेरेटिव डिसऑर्डर्ज जो हाथ के लकवे तथा इसकी मासपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप-पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,–

I. क्रम संख्या 2 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (1) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(1) 10+2;";

II. क्रम संख्या 3 के सामने,–

(क) खाना 3 के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"(1) 10+2;

(2) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;

(3) नियम 9 क के दृष्टिगत लोप कर दिया गया है।";

(ख) खाना 4 के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"(1) 10+2;

(2) श्रेणी IV पद पर पाँच वर्ष का अनुभव;

(4) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।"।

एस० सी० चौधरी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 8th November, 2013

No. G.S.R. 29/Const/Art.309/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana State Prosecution Group 'C' (Clerical Field) Service Rules, 1977, namely :-

1. These rules may be called the Haryana State Prosecution Group 'C' (Clerical Field) Service (Amendment) Rules, 2013.

2. In the Haryana State Prosecution Group 'C' (Clerical Field) Service Rules, 1979 (hereinafter called the said rules), after rule 9, the following rule shall be inserted, namely :—

"9A (1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers in the Government Departments/Organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. who have not passed the typing test till date as required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Application (SETC). The Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Sr. Scale Stenographers shall also have to qualify Stenography test as prescribed in the Service Rules.

(2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Application (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruit. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk and Steno-typist shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year, failing which he/she will be reverted back.

(3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTON) or any other agency as prescribed by the Government, as the authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as the State Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The 'pass' certificate

issued by HARTON or any other agency, as approved by the Government, would be accepted as an evidence of the fulfillment of the prescribed condition in the Service Rules.

(4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.

(5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed would be tested on computers.

(6) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) :—

(i) M.Tech./B.Tech (Computers), MCA, BCA or Diploma in Computers from the recognized institutions e.g. Polytechnics;

(ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];

(iii) Haryana State – Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorized Learning Centres (ALCs) of the HKCL;

(iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of 5 years from the date of issue of such certificate by HARTON or any other agency authorized by the Government; and

(v) Physically disabled candidates i.e. amputation of hand (left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial Nerve (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC)."

3. In the said rules, in Appendix B, —

I. against serial number 2, under column 3, for existing item (1), the following item shall be substituted, namely :-

"(1) 10+2;";

II. against serial number 3, -(a) under column 3, for existing item, the following item shall be substituted, namely :-

"(1) 10+2;

(2) Knowledge of Hindi upto Metric standard;

(3) Omitted in view of rule 9A;";

(b) under column 4, for the existing item, the following items shall be substituted, namely :-

"(1) 10+2;

(2) Five year experience on Class IV post;

(3) Knowledge of Hindi upto Metric standard.".

S. C. CHOUDHARY,
Additional Chief Secretary to Government
Haryana, Administration of Justice Department.

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 सितम्बर, 1996

संख्या सा० का० नि० 88/संवि०/अनु० 309/96.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग (ग्रुप "घ") सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

भाग I—सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य अभियोजन (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1996 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा आरम्भ।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही सर्व किसी पदाधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ख) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक अभियोजन, हरियाणा;

(ग) "रोजगार कार्यालय" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य में जिला हरियाणा रोजगार कार्यालय,

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार; और

(ङ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य अभियोजन (ग्रुप घ) सेवा।

भाग—II

सेवा में भर्ती

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताए गए पद होंगे: पदों की संख्या तथा स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो:

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा में या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था से, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाणपत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से उससे भली-भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय/विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो किसी भर्ती प्राधिकरण को आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से पूर्व के अगले मास के प्रथम दिन को या उससे पूर्व 18 वर्ष की आयु से कम का, या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

परन्तु अधिकतम आयु की सीमा में सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई हिदायतों के अनुसार छूट दी जा सकती है।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जाएंगी।

अर्हताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी। यदि

अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,— निरर्हताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार को संतुष्टि हो जाए कि ऐसा व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी:— भर्ती का ढंग।

(क) सेवादार की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) स्वीपर एवं चौकीदार की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, सभी पदोन्नतियां ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा : परिवीक्षा।

परन्तु,—

(क) परन्तु ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकरण के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी : ज्येष्ठता।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(ग) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा। सेवा करने का दायित्व।

(2) सेवा के किसी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास हो,

हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम, स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संगठन या अन्य निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाये गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जायें ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में बताया गया हो ।

टीका लगवाना ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे तो टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा ।

राजनिष्ठा की शपथ ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

ढील देने की शक्ति।

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:

परन्तु इस प्रकार किए गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

20. सेवा को लागू कोई नियम और इन नियमों में से, किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा निरसित किया जाता है:

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	सेवादार	16	46	62	750—12—870—द. रो.—14—940 रुपए
2	सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार	..	1	1	750—12—870—द. रो.—14—940 रुपए

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव यदि कोई हों	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव यदि कोई हों
1	2	3	4
1	सेवादार	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान
2	सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	सेवादार	निदेशक	1. छोटी शास्तियां — (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ; 2. बड़ी शास्तियां— (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना;	निदेशक	सरकार
2	सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार				

1	2	3	4	5	6
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं; (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा; (ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ; (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ; (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।		

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	शास्ति का स्वरूप	शास्ति पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	चपड़ासी	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना	निदेशक	सरकार
2.	सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार	(ii) सेवा के सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से पहले नियुक्ति की समाप्ति।		

मीनाक्षी आनन्द चौधरी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 20th September, 1996

No. G.S.R.86/Const./Art. 309/96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following Rules,—regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Prosecution (Group D) Service, namely:—

PART I—GENERAL

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana State Prosecution Group 'D' Service Rules, 1996.

(2) They shall come into force at once.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'direct recruitment' means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government ;

(b) 'Director' means the Director of Prosecution, Haryana ;

(c) 'Employment Exchange' means the Haryana Employment Exchange, situated in Haryana State;

(d) 'Government' means the Haryana Government in the Administration of Justice Department ; and

(e) 'Service' means the Haryana State Prosecution Group D Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts.

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these Rules:

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make additions, to or reduction in the number of such posts or, to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the first day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or Board or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal, Academic Officer of the University, College, School or Institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relative who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or Institution.

5. No person shall be appointed to the post in the Service by direct recruitment who is less than 16 years or more than 35 years of age on or before the first date of the month next preceding the last date fixed for submission of application to any recruiting authority — Age.

Provided that the maximum age shall be relaxable in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.

6. Appointment to the posts in the service shall be made by the Director. — Appointing authority.

7. No person shall be appointed to the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment ; — Qualification.

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and physically handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualification.

8. No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage, with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any post in the service ;

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the service shall be made

(a) In case of Peons,

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(b) In case of Sweeper-cum-Chowkidar.—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided shall be made on the seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotion in respective cadre.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that :—

(a) any period, after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in any post in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as a period spent on probation, but no person who has so officiated shall on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may :—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, or revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit, if appointed otherwise ;

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

11. The Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service ; Seniority

Provided that where there are different cadres in the service, the seniority shall be determined separately for each cadre ;

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by transfer ;

(b) in the case of member appointed by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were transferred ;

(c) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to service.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under:—

(i) a company, association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a Local Authority or University within the State of Haryana ; or

(ii) the Central Government or a Company, Association or body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body

Provided that no member of the service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, Leave, Pension and other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the Competent Authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and Appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority

shall, subject to the provisions of any law or rules made under Article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix 'C' to these Rules.

(2) The authority competent to pass an order under clauses (c) and (d) of Sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall be as specified in Appendix 'C' to these Rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

Special provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and savings.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules, is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX 'A'

(*See* rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts Perma-nent	Tempo-rary	Total	Scale of pay
1	2	3	4	5	6
1	Peons	16	46	62	Rs. 750—12—870—EB—14—940
2	Sweeper-cum-Chowkidar	—	1	1	Rs. 750—12—870—EB—14—940.

APPENDIX 'B'

(*See* rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Peon	Knowledge of Hindi and English	Knowledge of Hindi and English
2.	Sweeper-cum-Chowkidar	Knowledge of Hindi and English	Knowledge of Hindi and English

APPENDIX 'C'

(*See* Rule 14)

Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penality	Authority empowered to impose penality	Appellate Authority
1	2	3	4	5
		1. **Minor penalities**		
1 Peons	Director	(i) Warning with a copy on the personal file (character role);	Director	Government
2 Sweeper-cum-Chowkidar	Do	(ii) Censure ;		
		(iii) withholding of promotion;		
		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence of breach of order, to the Central Government or State Government or to a Company and Association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and		
		(v) withholding of increments without cummulative effect;		
		2. **Major penalities** ;		
		(vi) withholding of increments with cummulative effect ;		

1	2	3	4	5	6
		(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have effect of postponing the future increments of his pay ;			
		(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post of service from which the Government employee was reduced, and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;			
		(ix) compulsory retirement;			
		(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;			
		(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for furture employment under the Government.			

APPENDIX 'D'

[*See* Rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to ma the Order	Appellate Authority
1	2	3	4	5
1 2	Peons Sweeper-cum-Chowkidar	(1) reducting or with-holding the amount of ordinary/additional pension admissible under the rules, governing pension. (2) determinating the appointment of otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Director	Government

MEENAXI ANAND CHAUDHRY, IAS,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

PART III
HARYANA GOVERNMENT
ADMINSTRATION OFJUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 10-Dec 2009

No. G.S.R/Const./Art. 309/2009. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Prosecution (Group D) Service Rules, 1996, namely:-

1. These rules may be called the Haryana State Prosecution (Group D) Service (First Amendment) Rules, 2009.

2. In the Haryana State Prosecution (Group D) Service Rules, 1996, in Appendix B, against serial No. 1&2, under Column 3&4, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:-

(i) Middle pass with Hindi.

(Krishna Mohan)
Financial Commissioner & Principal Secretary to Government Haryana, Administration of Justice Department

भाग–III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 Dec. 2009

संख्या सा0का0नि0/संवि0/अनु0 309/2009 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अभियोजन (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1996, को आगे संशोधित करने के निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:–

1. ये नियम हरियाणा राज्य अभियोजन (ग्रुप घ) सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2009, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य अभियोजन (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1996 में, परिशिष्ट ख में, क्रम संख्या 1 एवं 2 के सामने, खाना 3 एवं 4 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:–

(i) आठवीं पास हिन्दी सहित।

(कृष्ण मोहन)

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग।